cases were detected. Actions such as issuing warning to concerned traders, levying fine for renewal of registration, issuing show cause notice etc. were taken by the Board.

मुरादाबाद के पीतल के बर्तनों का निर्यात

3327. **श्री मोहम्मद अफजल उर्फ शीम अफजल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुरादाबाद के कितने मूल्य के पीतल के बर्तनों का निर्यात किया गया है; और

(ख) उक्त बर्तनों का किन-किन देशों को निर्यात किया गया था ?

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री कमालुद्दीन अहमद) :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पीतल के बर्तनों, ई पी एन एस वेयर और तांबे के बर्तनों का निर्यात निम्नानुसार रहा :—

(मूल्य करोड़ रु. में)

मद	1990–91	1991–92	अप्रैल सितम्बर, 1992
ई० पी० एन० एस० वेयर	24.96	41.01	23.40
पीतल के बर्तन	0.30	0.36	0.36
तांबे के बर्तन	0.26	0.51	0.37
योग	25.52	41.88	24.13

(स्रोत : इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद)

(ख) उपर्युक्त मदों का 30 से भी अधिक देशों को निर्यात किया जा रहा है । इनमें से प्रमुख देश ये हैं—संयुक्त राज्य अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कानाडा, ब्रिटेन, यूनान, हांगकांग, स्वीडन, इजराइल, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर और डेनमार्क ।

Performance of E.O.Us and FIZs

3328. SHRI SATISH PRADHAN : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have evaluated the performance of 100 per cent Export Oriented units in different sectors and Free Trade Zones over the year;

(b) if so, what are the main achievements and operational/administrative drawbacks of the schemes and the action taken proposed to be taken thereon;

(c) whether to make up for shortcomings Government are seriously considering to set up a Free Port in the country to take advantage of liberalisation and globalisation process on the economic front; and

(d) the details of the decision taken/proposed to be taken in the matter

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE) : (a) Yes, Sir.

(b) Exports by units in Export Processing Zones/Free trade zones and EOUs increased from Rs. 1602.7 Crores in 1990-91 to Rs. 2157.1 Crores in 1991-92. To cope with the changing international scenario, units under these schemes require a smooth working environment, as well as fiscal and other supports to increase competitiveness. Steps taken with this in view, inter-alia, include speedier approval procedures, simplification of policy framework, 100% foreign equity participation,